

माल उभादा तोलते है और बताते कम है, और

(ख) जी हा ।

(ग) यदि हा, तो शिकायतो का स्वरूप क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

(ग) और (घ) : प्रस्ताव की मुख्य बात, हायर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए निशुल्क करना है । इस योजना पर अमल करने के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक खर्च इस प्रकार होगा

कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) : देश भर में भारतीय खाद्य निगम और अन्य अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की अत्यधिक अधिप्राप्ति की जा रही है । सरकार को कुछेक शिफायते मिली है जिनमें किसानों को परेशान करने, गेहूँ न खरीदने, कम रमीड जारी करने, बिना औचित्य के गेहूँ का कम श्रणीकरण करने या उसे अस्वीकार करने, सही मूल्य का भुगतान न करने, रिभवत लेने आदि के बारे में आरोप लगाए गए हैं । इन शिकायतों को तत्परता से जाच की जाती है और यहाँ आवश्यक होता है, उन मामलों में उपयुक्त उपचारों उपाय किए जाते हैं ।

राजकीय स्कूलों से प्राप्त होने वाले राजस्व का घाटा 65 लाख रुपये

महायता प्राप्त स्कूलों को अतिरिक्त सहायक अनुदान की अदायगी । 35 लाख रुपये

इस योजना पर अमल करना अन्य बातों के साथ-साथ धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

दिल्ली में निशुल्क उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

New Schemes launched by National Cooperative Development Corporation

7025. श्री चन्दा लाल चन्द्राकार : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

7026 SHRI JYOTIRMOY BOSU . Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state

(क) क्या शिक्षा मन्त्रालय ने दिल्ली प्रशासन से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निशुल्क करने को कहा है ,

(a) whether the National Cooperative Development Corporation have launched two new schemes, involving Rs 175 crores to increase the storage capacity and strengthen the share capital base of the cooperatives, and

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस प्रकार की मांग केन्द्रीय सरकार ने की है ,

(b) if so, the main features thereof ?

(ग) यदि हा, तो उसका पूरा व्यौरा क्या है और उसमें कितना व्यय अधिक होने की सम्भावना है, और

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAGANNATH PAHADIA) (a) It has been decided to implement two new Central Sector Schemes for (i) cooperative storage and (ii) strengthening the share capital base of cooperative marketing societies, involving a total outlay of Rs 175 crores during the last two years of the Fourth Five Year Plan. Both the schemes will be operated by the National Cooperative Development Corporation on behalf of the Central Government and Central assistance to State Governments will be channelised through the Corporation.

(घ) इस योजना के कब तक लागू होने की सम्भावना है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० शारदा) : (क) जी, नहीं ।